भारत-चीन संबंध- चुनौतियाँ और उभरते मुद्दे

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विशेषण किया गया है। इस लेख में भारत चीन संबंधों और हालिया अनौपचारिक शिखर सम्मेलन पर चर्चा की गई है। साथ ही इसमें दोनों देशों के मध्य चुनौतियों और अन्य उभरते मुद्दों का भी उलेख किया गया है। आवश्यकतानुसार, यथार्थता टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किए गए हैं।

संदर्भ

हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे, जहाँ उन्होंने तमिलनाडू के महाबलीपुरम (मामल्लपुरम) में भारतीय प्रधानमंत्री के साथ एक अनौपचारिक वार्ता में हिस्सा लिया। उलेखनीय है कि इस प्रकार की अनौपचारिक वार्ताओं की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी और ये दोनों प्रतिनिधियों को द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक महत्व के अतिव्यापी मुद्दों पर चर्चा जारी रखने का अवसर प्रदान करते हैं।

हालिया अनौपचारिक शिखर सम्मेलन

- भारत और चीन के मध्य यह दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन तमिलनाडू के महाबलीपुरम (मामल्लपुरम) में आयोजित किया गया था।
- उलेखनीय है कि इससे पूर्व वर्ष 2018 में पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन चीन के शहर वुहान में संपन्न हुआ था।
- विदेश मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इस अनौपचारिक सम्मेलन में दोनों नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के अतिव्यापी, दीर्घकालिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की।

महाबलीपुरम और उसका महत्व

- भारत ने मामल्लपुरम को भारत की ' सॉफ्ट पॉवर' (Soft Power) के प्रतीक के रूप में चुना।
- मामल्लपुरम या महाबलीपुरम पूर्ववर्ती पत्थर वंश, जिसने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में 275 CE से 897 CE तक शासन किया, के काल का एक महाकाल पूर्व है।
- यह दुनिया भर में अपनी बास्तुकला के लिये काफी प्रसिद्ध है।
- उलेखनीय है कि महाबलीपुरम पुरातन काल में काफी प्रसिद्ध बंदरगाह था और सितक रुट का हिस्सा होने के कारण भारत का यह क्षेत्र (महाबलीपुरम) चीन और कई अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार करता था।
भारत चीन संबंधों का विकास

- ध्यात्मवाद है कि हजारों वर्षों तक तिब्बत ने एक ऐसे क्षेत्र के रूप में काम किया जिसने भारत और चीन को भौगोलिक रूप से अलग और शांत रखा, परंतु जब वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर वहाँ कब्जा कर लिया तब भारत और चीन आपस में सीमा साझा करने लगे और पड़ोसी देश बन गए।
- वृद्धि के मध्य तक भारत और चीन के बीच संबंध न्यूतरम थे एवं कुछ व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और विद्वानों के आवागमन तक ही निर्मित थे।
- दोनों देशों के मध्य व्यापक तौर पर बातचीत की शुरुआत भारत की स्वतंत्रता (1947) और चीन की कम्यूनिस्ट क्रांति (1949) के बाद हुई।
- भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक स्वतंत्र तिब्बत के पक्ष में थे, नेहरू जी के इस विचार ने शुरुआती दौर में भारत और चीन के संबंधों को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उल्लेखनीय है कि भारत और तिब्बत के मध्य आधारित संबंध चीन के लिए सही का विषय था।
- वर्ष 1954 में नेहरू और जोआो एन्लाई ने "हिंदी-चीनी-भाई-भाई" के नामों के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किये, ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिये कार्ययोजना तैयार की जा सके।
- वर्ष 1959 में तिब्बती लोगों के आधारित और लौटक का प्रभुक्त दलाई लामा तथा उनके साथ अन्य कई तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए। इसके पश्चात चीन ने भारत पर तिब्बत और पूरे हिमालयी क्षेत्र में विस्तारण और सामरिकवाद के अध्ययन का आरोप लगा दिया।
- चीन ने भारत के मानचित्र में प्रदर्शित 104,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर दा वार प्रस्तुत किया और दोनों देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संशोधन की मांग की।
- वर्ष 1962 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लड़ाई और तेल्पालीन नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एर्जनेटी में मैक्सन रेखा के पास भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद दोनों देश के मध्य युद्ध शुरु हो गया और ऐसा करने और अधिक खरब स्थिति में पहुँच गई।
- वर्ष 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ऐतिहासिक यात्रा ने दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के एक नये चरण की शुरुआत की और उसके माध्यम से भारत और चीन के संबंध पुनः सामान्य होने लगे।

विभिन्न क्षेत्रों पर भारत-चीन संबंध

राजनीतिक संबंध

भारत ने 1 अप्रैल, 1950 को चीन के साथ अपने राजनीतिक संबंध स्थापित किये थे और इसी के साथ भारत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर-सामाजिक देश बन गया था। वर्ष 1962 में भारत और चीन के मध्य सीमा संघर्ष की शुरुआत दोनों देशों के संबंधों के लिये एक नई झड़ी झड़ी थाई। परंतु वर्ष 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ऐतिहासिक यात्रा ने दोनों देशों के मध्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि वर्तमान संबंध में बात करने तो दोनों देशों के प्रतिनिधियों के मध्य समय-समय पर द्विपक्षीय वातावरणों के साथ-साथ अनौपचारिक सम्मेलनों का आयोजन भी किया जा रहा है, जो वह दर्शाता है कि दोनों देश अपने दीर्घकालिक इतिहास को लेकर सजाया है।

वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध

भारत और चीन ने वर्ष 1984 में एक व्यापार सम्मेलन पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत उन्हें मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा प्रदान किया गया। इसके पश्चात वर्ष 1994 में दोनों देशों ने दोस्ती करारस्वाद से बने ने से लिये भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। भारत और चीन के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों में चितल कुछ वर्षों में तेजी देखी गई है। वर्ष 2000 की शुरुआत में दोनों देशों के बीच 3 बिलियन डॉलर का व्यापार था, जो कि वर्ष 2017 में बढ़कर 84.5 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।
सांस्कृतिक संबंध

भारत और चीन के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान की शुरुआत कई शास्त्रीयों पहले हुई थी। कुछ ऐसे भी साक्ष्य मौजूद हैं जो भारत के प्राचीन वैदिक समयों और चीन की शान-झोल समय के मध्य 1500-1000 ई.पू. के आस-पास वैशालिक और भारतीय आदान-प्रदान को दर्शाते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान कई बीच तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने ऐतिहासिक 'शेष मार्ग' के माध्यम से चीन की यात्रा की। इसी तरह कई चीनी यात्री जैसे- इंटियंग, फाह्स्क और हेनसांग आदि भारत की यात्रा पर आए। इसके अलावा शैक्षिक आदान-प्रदान हेतु वर्ष 2003 में पाकिस्तान विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन केंद्र की भी स्थापना की गई थी। चीन में भी योग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उल्लेखित है कि 21 जुलाई के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में नामित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के सह-प्राप्तियों में चीन भी एक था। भारतीय फिल्मों में भी चीन में काफी लोकप्रिय हैं और वहाँ काफी अच्छी कमाई करती हैं।

शैक्षिक संबंध

भारत और चीन ने वर्ष 2006 में एयूक्शन एक्सचेंज प्रोग्राम (EEP) पर हस्ताक्षर किया, ज्ञात्वय है कि यह दोनों देशों के बीच शैक्षिक सहयोग को बढ़ाने हेतु किया गया एक समझौता है। इस समझौते के तहत भारत और चीन एक-दूसरे के देश में उच्च शिक्षा के मान्यता प्राप्त संस्थाओं के 25 छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष उंच में सहयोग के परिणामस्वरूप चीन में भारतीय छात्रों की संख्या में आबादी हुई है। आर्कोड्स के अनुसार, शैक्षिक वर्ष 2016-17 के दौरान चीन के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुल 18171 भारतीय छात्र विश्वविद्यालयों में अध्ययनमंत्र थे।

भारत-चीन संबंध- चिंताएँ

तिब्बत और दलाई लामा

- उल्लेखित है कि चीन अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर सदैव ही काफी संवेदनशील रहा है। तिब्बत पर भारत का शुरुआती पक्ष और भारत द्वारा दलाई लामा का शरण देना ऐतिहासिक रूप से चीन के लिए चिता का विषय रहा है।
- वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर वहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी और पंडित नेहरू ने उस समय तिब्बत की स्वतंत्रता का पक्ष लिया था।
- चीन दलाई लामा (जिनका तिब्बतीयों पर गहरा प्रभाव है) को अत्याचारी भावना मानता है।
- तिब्बती श्राधार्थियों के पुनर्वास में भारत की भूमिका को लेकर चीन का स्वतंत्र व्यवहार से आलोचनात्मक रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय निकायों और मानवाधिकार समूहों ने भारत के इस कदम की प्रशंसा की है।

सीमा विवाद

- भारत और चीन के मध्य असाइ चिन तथा असाई चिन में सीमा विवाद भी है। दोनों ही देश दोनों क्षेत्रों पर अपना-अपना दाया प्रस्तुत करते हैं, ज्ञात्वय है कि वर्तमान में असाइ चिन, चीन के पास है, जबकि असाई चिन भारत के पास।
- मई 2015 में जब भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया था, तो उनका एक मुख्य उद्देश्य चीन के शीर्ष नेतृत्व को वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के स्पष्टकरण पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करना भी था।

जल विवाद

- भारत और चीन के बीच जल विवाद मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है जो दोनों देशों से होकर बहती है।
• बीते कुछ वर्षों में कई बार ऐसी खबरें सामने आती रही हैं कि चीन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह को रोकने के उद्देश्य से अंध का निर्माण कर रहा है और यदि ऐसा होता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जल की आपूर्ति बाधित हो सकती है, यही दोनों पक्षों के मध्य विवाद का एक बड़ा कारण बना हुआ है।

दक्षिण चीन सागर का मुदा

• चीन, दक्षिण चीन सागर के 90 प्रतिशत हिस्से को अपना मानता है। यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक तेल और गैस सुधार मात्रा में उपलब्ध हैं।
• चीन, ताइवान और विदेश नाम स्प्राइल ड्रीपसमूह पर अपनी दावेदारी जताते रहे हैं। विविध हो कि स्प्राइल, दक्षिण चीन सागर का दूसरा सबसे बड़ा ड्रीपसमूह है।
• उलेखनीय है कि भारत विदेश नाम के अनुरोध पर दक्षिण चीन सागर में तेल का अन्वेषण करता है और चीन हमेशा से भारत के इस कदम की आलोचना करता रहा है।

भारत और चीन- सहयोग क्षेत्र

• दोनों देशों के मध्य प्रतिद्वंद्विता के बावजूद उन्होंने सांस्कृतिक स्तर पर काफी अच्छा सहयोग किया है, उलेखनीय है कि भारत में जन्मा बाल धर्म चीन में काफी लोकप्रिय है।
• दोनों ही देश धनुष उपयोग की अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स (BRICS) का हिस्सा हैं। ध्यात्मक है कि वर्ष 2014 में ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शांताइ (चीन) में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष के वी कामथ (एक भारतीय) है।
• ध्यान है कि भारत चीन समर्थन एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेटमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य भी था।

भारत की विदेश नीति और चीन

भारत ने चीन से निपटने के लिये दोस्तता नीति अपनाई है। इस नीति के तहत एक ओर भारत चीन के साथ आर्थिक संबंधों को बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर कूटनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिये ब्रिक्स, एससीओ (SCO) तथा रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय जैसे मंचों से लगातार जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भारत ने अपनी सैन्य और निर्माता क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयासों को नीति के दूरसे पक्ष के रूप में कामयाब रखा है।

व्यापार घाटा- एक बड़ी चिंता

बीते दो दशकों में भारत और चीन के बीच व्यापार काफी तेजी से बढ़ा है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ एक ओर वर्ष 2000 में चीन के साथ भारत का कुल व्यापार सिर्फ 3 बिलियन डॉलर था, वहाँ वर्ष 2008 में यह बढ़कर 51.8 बिलियन डॉलर पहुँच गया। इस प्रकार चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत के साथ व्यापार करने वाला सबसे बड़ा साझेदार बन गया। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी ऑक्टॉबर के अनुसार, वर्ष 2018 में दोनों देशों का कुल व्यापार 95.54 बिलियन डॉलर का था, परंतु इसके भारत द्वारा कुल विनियम मात्रा 18.84 बिलियन डॉलर का था अर्थात् चीन ने भारत से जितला सामान खरीदा उससे पूर्ण गुणा सामान बेचा। उलेखनीय है कि भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा भी चीन के साथ ही है, वर्ष 2018 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 57.86 बिलियन डॉलर का था।

धारा 370 और चीन

कश्मीर को लेकर चीन का कहना है कि इस विषय को संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेज़ोल्यूशन और द्विपक्षीय समझौते के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। कुछ ही महीनों पूर्व जब जम्मू-कश्मीर की विशेषाधिकार संबंधी धारा 370 को
वनस्पति किया गया था, तब चीन का कहना था कि भारत ने चीन की संप्रभुता संबंधी चिंताओं का उल्लंघन किया है। चीन की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि वह लड़ाकू पर अपने दावों को दोहरा रहा था। इसके अतिरिक्त हाल ही में चीन ने कश्मीर और धारा 370 का विषय संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी उठाया था और कहा था कि हम जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं।

चीन का हॉन्काओंग संकट और भारत

भारत का रूख चीन की हॉन्काओंग नीति के प्रति उदासीन रहा है। भारत ने कभी भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन नहीं किया है, जबकि अन्य देश खुलकर हॉन्काओंग के लोगों का समर्थन करते रहे हैं। चीन के साथ भारत पहले से उपस्थित मतभेदों को बढ़ाना नहीं चाहता है, इसलिए चीन का रूख कश्मीर जैसे विभिन्न मुद्दों पर भारत की तरफ रही है तथा वह हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा रहा है। एक ओर चीन कश्मीर युद्ध का अंतरराष्ट्रीय करण करना चाहता है, यह जब उन्हीं उड़ियों तथा हॉन्काओंग के मामले में अमानवीय रूप आखिरी करता है। भारत की भी चीन के रूख के अनुसार ही अपनी नीति का निर्माण करना चाहिये। यदि चीन कश्मीर युद्ध पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है तो भारत को भी हॉन्काओंग का खुलकर समर्थन करना चाहिये।

वन बेल्ट वन रोड (OBOR) और भारत

वन बेल्ट वन रोड (OBOR) पहल चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढाँचा विकास एवं संपर्क परियोजना है जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल एवं जलमार्गों के माध्यम से मूलों, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है, परंतु भारत अब तक इस पहल में शामिल नहीं हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन की OBOR पहल में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) को भी शामिल कर लिया गया है। बूँदके CPEC गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। अतः OBOR में शामिल होने का मतलब है कि भारत द्वारा इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के अधिकार को सहमति प्रदान कर देना, जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। इसके अलावा OBOR वास्तव में चीन द्वारा परियोजना निर्माण (Project Export) का माध्यम है जिसके जरिये वह अपने विशाल विदेशी मुद्रा बंडरों का प्रयोग बदनानों के विकास, औद्योगिक केंद्रों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) के विकास के लिए कर वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, जो कि दीर्घकाल में भारत के हित में नहीं होगा।

प्रश्न: भारत-चीन संबंधों की चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिये कि क्या लगातार बदल रहे भू-राजनीतिक परिस्थिति के कारण भारत को अपनी चीन संबंधी विदेश नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है?